

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4871
दिनांक 01 अप्रैल, 2022 को उत्तर के लिए

कुपोषित बच्चे

4871. श्री जुगल किशोर शर्मा:

श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:

श्रीमती गीता कोडा:

श्रीमती रीती पाठक:

श्री डी. के. सुरेश:

डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने सम्पूर्ण देश में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण के स्तर का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन या सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणाम क्या रहे;
- (ख) क्या भारत में 33 लाख बच्चे कुपोषित हैं और उनमें से आधे से अधिक गंभीर रूप से कुपोषित श्रेणी में आते हैं;
- (ग) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुपोषित बच्चों का प्रतिशत दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) देश में वे जिले और राज्य कौन से हैं जहाँ कुपोषित बच्चों की संख्या अधिकतम/ न्यूनतम है; और
- (ङ) सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश में बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए अब तक क्या उपाय किये गए हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़बिन इरानी

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) : देश में पांच साल से कम आयु के बच्चों और महिलाओं (15-49 वर्ष) में कुपोषण (ठिगनापन, दुबलापन और अल्पवजन) का स्टेटस स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर संचालित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। एनएफएचएस-5 (2019-21) के अनुसार पांच साल से कम आयु के बच्चों के लिए पोषण के संकेतकों में एनएफएचएस-4 (2015-16) की तुलना में सुधार हुआ है। ठिगनापन, दुबलापन और अल्पवजन क्रमशः 38.4 प्रतिशत से घटकर 35.5 प्रतिशत, 21 प्रतिशत से घटकर 19.3 प्रतिशत और 35.8 प्रतिशत से घटकर 32.1 प्रतिशत हो गया है। इसके अलावा 15-49 वर्ष के आयुवर्ग की महिलाओं में कुपोषण की दर 22.9 प्रतिशत (एनएफएचएस-4) से घटकर 18.7 प्रतिशत (एनएफएचएस-5) हो गई है।

(ख) : राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) के अनुसार पांच साल से कम आयु के 19.3 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं, जबकि लगभग 7.7 प्रतिशत बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित श्रेणी में हैं।

(ग) : एनएफएचएस-5 के अनुसार पांच साल से कम आयु के बच्चों में ठिगनेपन, दुबलेपन और अल्पवजन की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दर अनुलग्नक I में दी गई है।

(घ) : ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण अनुलग्नक II में दिया गया है जहां कुपोषित बच्चों की संख्या सबसे अधिक और सबसे कम है।

(ड.) : सरकार ने कुपोषण की समस्या को उच्च प्राथमिकता दी है तथा देश में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए प्रत्यक्ष लक्षित उपाय के रूप में अंब्रेला समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम के तहत आंगनवाड़ी सेवा, किशोरियों के लिए स्कीम और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएएमवीवाई) जैसी अनेक स्कीमें चला रही है। गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों का उपचार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्थापित पोषण पुनर्वास केंद्रों में किया जाता है।

08 मार्च, 2018 को शुरू किए गए पोषण अभियान का उद्देश्य तालमेल युक्त और परिणामोन्मुख दृष्टिकोण अपनाकर पूरे जीवनचक्र में चरणबद्ध ढंग से देश में कुपोषण को कम करना है।

मिशन पोषण 2.0 जो एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए बजट 2021-22 में घोषित किया गया है। यह स्वास्थ्य, आरोग्यता और बीमारी एवं कुपोषण के प्रति प्रतिरक्षण को बढ़ावा देने वाली प्रथाओं के विकास पर बल देते हुए पोषण सामग्री, वितरण, आउटरीच और परिणामों को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। इसके अलावा पूरक पोषण के वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए तथा पोषण परिणामों की खोज-खबर लेने के लिए 13.01.2021 को दिशा-निर्देश जारी किए गए।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) के अनुसार पांच साल से कम आयु के बच्चों में ठिगनेपन, दुबलेपन और अल्पवजन की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दर

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संकेतक		
		ठिगनापन (%)	दुबलापन (%)	अल्पवजन (%)
	भारत	35.5	19.3	32.1
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	22.5	16	23.7
2	आंध्र प्रदेश	31.2	16.1	29.6
3	अरुणाचल प्रदेश	28	13.1	15.4
4	असम	35.3	21.7	32.8
5	बिहार	42.9	22.9	41
6	चंडीगढ़	25.3	8.4	20.6
7	छत्तीसगढ़	34.6	18.9	31.3
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	39.4	21.6	38.7
9	दिल्ली	30.9	11.2	21.8
10	गोवा	25.8	19.1	24
11	गुजरात	39	25.1	39.7
12	हरयाणा	27.5	11.5	21.5
13	हिमाचल प्रदेश	30.8	17.4	25.5
14	जम्मू और कश्मीर	26.9	19	21
15	झारखंड	39.6	22.4	39.4
16	कर्नाटक	35.4	19.5	32.9
17	केरल	23.4	15.8	19.7
18	लक्षद्वीप	32	17.4	25.8
19	लद्दाख	30.5	17.5	20.4
20	मध्य प्रदेश	35.7	19	33
21	महाराष्ट्र	35.2	25.6	36.1
22	मणिपुर	23.4	9.9	13.3
23	मेघालय	46.5	12.1	26.6
24	मिजोरम	28.9	9.8	12.7
25	नगालैंड	32.7	19.1	26.9
26	ओडिशा	31	18.1	29.7
27	पुदुचेरी	20	12.4	15.3
28	पंजाब	24.5	10.6	16.9
29	राजस्थान	31.8	16.8	27.6
30	सिक्किम	22.3	13.7	13.1
31	तमिलनाडु	25	14.6	22
32	तेलंगाना	33.1	21.7	31.8
33	त्रिपुरा	32.3	18.2	25.6
34	उत्तर प्रदेश	39.7	17.3	32.1
35	उत्तराखंड	27	13.2	21
36	पश्चिम बंगाल	33.8	20.3	32.2

एनएफएचएस-5 (2019-21) के आधार पर ठिगनेपन, दुबलेपन और अल्पवजन में सर्वोत्तम और और कम निष्पादन वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार

ठिगनापन			
सर्वोत्तम निष्पादक		कम निष्पादक	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एनएफएचएस-5	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एनएफएचएस-5
पुदुचेरी	20	मेघालय	46.5
सिक्किम	22.3	बिहार	42.9
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	22.5	उत्तर प्रदेश	39.7
मणिपुर	23.4	झारखंड	39.6
केरल	23.4	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	39.4
पंजाब	24.5	गुजरात	39
तमिलनाडु	25	मध्य प्रदेश	35.7
चंडीगढ़	25.3	कर्नाटक	35.4
गोवा	25.8	असम	35.3
जम्मू और कश्मीर	26.9	महाराष्ट्र	35.2

दुबलापन			
सर्वोत्तम निष्पादक		कम निष्पादक	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एनएफएचएस-5	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एनएफएचएस-5
चंडीगढ़	8.4	महाराष्ट्र	25.6
मिजोरम	9.8	गुजरात	25.1
मणिपुर	9.9	बिहार	22.9
पंजाब	10.6	झारखंड	22.4
दिल्ली	11.2	असम	21.7
हरयाणा	11.5	तेलंगाना	21.7
मेघालय	12.1	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	21.6
पुदुचेरी	12.4	पश्चिम बंगाल	20.3
अरुणाचल प्रदेश	13.1	कर्नाटक	19.5
उत्तराखंड	13.2	नागालैंड	19.1

अल्पवजन			
सर्वोत्तम निष्पादक		कम निष्पादक	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एनएफएचएस-5	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एनएफएचएस-5
मिजोरम	12.7	बिहार	41
सिक्किम	13.1	गुजरात	39.7
मणिपुर	13.3	झारखंड	39.4
पुदुचेरी	15.3	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	38.7
अरुणाचल प्रदेश	15.4	महाराष्ट्र	36.1
पंजाब	16.9	मध्य प्रदेश	33
केरल	19.7	कर्नाटक	32.9
लद्दाख	20.4	असम	32.8
चंडीगढ़	20.6	पश्चिम बंगाल	32.2

अल्पवजन			
सर्वोत्तम निष्पादक		कम निष्पादक	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एनएफएचएस-5	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एनएफएचएस-5
जम्मू और कश्मीर	21	उत्तर प्रदेश	32.1